



दैनिक जागरण

विचार कर्म का आधार है

## फिर सिर उठाते आतंकी

कश्मीर में अनंतनाग के जिला उपायुक्त कार्यालय पर ग्रेनेड हमला यही बता रहा है कि तमाम सतर्कता के बावजूद आतंकीयों के दुस्साहस का दमन नहीं हो सका है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह दूसरा आतंकी हमला है। इस हमले में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें तीन की हालत गंभीर है। चूंकि किसी आतंकी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली इसलिए ऐसा लगता है कि वे सुरक्षा बलों की निगाह में आने से बचना चाह रहे हैं। सच्चाई जो भी हो, उन्हें सिर उठाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। वास्तव में ऐसा करके ही कश्मीर के हालात सामान्य किए जा सकते हैं। यह काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि कश्मीर पर लगी पाबंदियों को जल्द हटाया जा सके। आतंकीयों और उनके समर्थकों को नियंत्रित करने के साथ ही इसकी भी कोशिश होनी चाहिए कि घाटी के आम लोग अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ मुखर हों। इससे ही कश्मीर को लेकर जारी दुष्प्रचार थमेगा। केंद्र सरकार को इससे परिचित होना चाहिए कि इस दुष्प्रचार को भारत के साथ-साथ बाहर के भी कुछ लोग हवा देने में लगे हुए हैं। इसके लिए वे फर्जी खबरें गढ़ने का भी काम कर रहे हैं। कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार की एक वजह देश-दुनिया का इस तथ्य से अनभिज्ञ होना है कि अनुच्छेद 370 न केवल अर्थाई था, बल्कि उसके कुछ प्रावधानों को पहले भी शिथिल किया गया था।

वैश्विक मीडिया का एक हिस्सा इससे परिचित ही नहीं कि अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान किस तरह कश्मीरी जनता के साथ भेदभाव करते थे। वह इससे भी अनजान है कि अगर कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव अमल में नहीं लाया जा सका तो पाकिस्तान के कारण। निःसंदेह कश्मीर में बचे-खुचे आतंकीयों पर लगातार लगाने में सफलता तभी मिलेगी जब उनके साथ-साथ उनके छिपे-खुले समर्थकों से भी सख्ती से निपटा जाए। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके समर्थक और संरक्षक सीमा के उस पार भी हैं। वे कश्मीर का माहौल विगाड़ने की ताकत में भी हैं। पाकिस्तान उन्हें किस तरह उकसाने में लगा हुआ है, इसका पता गुलाम कश्मीर में शुरू किए गए धरना-प्रदर्शन से चलता है। पाकिस्तान सरकार प्रायोजित कश्मीर मार्च यही इंगित कर रहा है कि इमरान खान कश्मीर के बहाने अपने कुशासन से अपनी जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। वह एक ओर पाकिस्तानियों को सीमा पार करने से आगाह कर रहे हैं और दूसरी ओर इसकी भी कोशिश में हैं कि कश्मीर में हालात बिगड़ें ताकि उन्हें आसू बहाने का मौका मिले। चूंकि पाकिस्तान आसानी से नहीं सुधरने वाला इसलिए उसे कुछ और सख्त संदेश देने की जरूरत है।

## कार्रवाई में हीलाहवाली

उत्तरखंड में विश्वविद्यालयों पर उच्च और तकनीकी शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने की अहम जिम्मेदारी है। इसे ध्यान में रखकर ही सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को खोलने में खासी दरिमादिली दिखाई गई। बावजूद इसके शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल अनुरित है। आश्चर्यजनक यह है कि सरकारी विश्वविद्यालयों का इस मामले में प्रदर्शन ज्यादा खराब है। शैक्षिक प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त कर अपने परिसरों और संबद्ध कॉलेजों में पठन-पाठन को बेहतर बनाने, नई पहल और शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने में विश्वविद्यालयों की उदासीनता राज्य में उच्च व तकनीकी शिक्षा की स्थिति को काफी हद तक बयां कर जाती है। तकनीकी विश्वविद्यालय तो बदहाली का बड़ा उदाहरण ही बन गया है। विश्वविद्यालय में तमाम नियुक्तियों, संविदा और अस्थायी व्यवस्था पर रखे गए कार्मिकों को अहम और गोपनीय कार्यों को सौंपने के मामलों को लेकर तो अंगुली उठ ही रही थी, पीएचडी उपाधि में भी धांधली सामने आने के बाद विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा है। यही नहीं सरकार की ओर से कराए गए स्पेशल ऑडिट में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का खुलासा भी हो चुका है। विश्वविद्यालय की इस बदहाली ने राजभवन और शासन दोनों को ही सख्त रूख अपनाने को मजबूर किया। लिहाजा राज्यपाल की ओर से विश्वविद्यालय को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की सख्त हिदायत के साथ दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शासन ने भी गड़बड़ियों के मामले को कार्य परिपद में रखकर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश विश्वविद्यालय को दिए थे। उक्त दोनों ही आदेशों की नाफरमानी का अंदाजा इससे लग सकता है कि डेढ़ माह पहले शासन के निर्देशों का अब तक पालन नहीं हो सका है। इस वजह से ही राजभवन को कड़ा रूख अपनाने को मजबूर होना पड़ा है। लंबे अरसे तक विश्वविद्यालय में जिस तरह कामचलाऊ तरीके से व्यवस्था संचालित हुई है, उसका नतीजा शोध उपाधि की विश्वसनीयता और तमाम तरह की गड़बड़ियों के रूप में सामने है। ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई लाजिमी है। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ढुलमुल बना हुआ है, उससे सरकारी तंत्र भी कटघरे में है। तकनीकी शिक्षा को लेकर राज्य की छवि पर भी बुरा असर पड़ा है। सरकार को तकनीकी विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर गंभीर और सतर्क रहने की जरूरत है।

## निजता में सेंध लगाती तकनीक

मुकुल व्यास

आज अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन है, लेकिन इससे जुड़े प्राइवेंसी यानी निजता के मामलों के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। स्मार्टफोन हमारे मूवमेंट पर नजर रख सकता है। अब लोगों को यह चिंता हो गई है कि उनका स्मार्टफोन उनकी हर बात को सुन रहा है। अभी इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन उनकी चिंता निराधार नहीं है। दुनिया भर के शोधकर्ता ऑडियो का विश्लेषण करने वाले नए किस्म के शक्तिशाली एआई कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित कर रहे हैं जो सिर्फ ध्वनि से बहुत कुछ सूचनाएं निकाल सकते हैं।

यह नई टेक्नोलॉजी प्राइवेंसी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि इसकी उपस्थिति चीबीसों घंटे रहेगी। आवाज सुनने वाली एआई लोगों द्वारा बोले जाने वाले प्रत्येक शब्द का विश्लेषण करने के बजाय उनकी ध्वनि से ही बहुत सी व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त कर सकती है। इनमें आपकी लोकेशन से लेकर भाषा जैसी जानकारीयें शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सारी सूचनाएं आपके बोलने से निकलने वाली आवाज से ही प्राप्त की

स्मार्टफोन ऑडियो विश्लेषण वाली एआई तकनीक तमाम जानकारियां जुटा सकती है जो निजता के लिए बड़ा खतरा है

जा सकती हैं। इतना ही नहीं, ऑडियो एआई सिस्टम यह भी पता लगा सकता है कि कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे। यह आपके स्वास्थ्य और फिटनेस का विश्लेषण कर सकता है। आपको मौजूदा भावनात्मक दशा को जान सकता है और यह भी पता लगा सकता है कि आप नशे में हैं या नहीं। कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जो पता लगा सकते हैं कि खाते वक्त फोन पर बोलते हुए आप वास्तव में कौन सी चीज खा रहे थे। कुछ शोधकर्ता ऐसे सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो ध्वनि के विश्लेषण से लोगों का निदान कर सकेंगे।

कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जो बातचीत में वक्ता के एटीट्यूड का पता लगा सकते हैं और वक्ताओं के बीच टकराव का पता लगा सकते हैं। पिछले वर्ष विकसित किया गया एक एआई सिस्टम किसी दंपती के बीच आपसी बातचीत



संजय गुप्त

हम सबको इसे लेकर चेतना ही होगा कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी असर ने भारत की दहलीज पर दस्तक दे दी है

पटना में आई भीषण बाढ़ ने जहां शहरी आधारभूत ढांचे की पोल खोल दी वहीं यह भी साफ कर दिया कि तेजी से बिगड़ता पर्यावरण गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है। जब बारिश और बाढ़ से पटना के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जलप्रलय की स्थिति है तब देश के कुछ हिस्सों में सूखे जैसे हालात हैं। पिछले एक दशक में देश-दुनिया में तमाम स्थानों पर जरूरत से ज्यादा बारिश के कारण जान-माल की व्यापक क्षति हुई है। इसी दौरान यूरोपीय देशों में गर्मी के रिकॉर्ड भी टूटे हैं। पिछले वर्ष केरल में बारिश से हुई तबाही को हम भूल नहीं सकते। वहां अगस्त के शुरुआती 19 दिनों में ही 758.6 मिलीमीटर बारिश हुई जो सामान्य से 164 फीसद अधिक थी। इसके चलते जो बाढ़ आई उसमें तीन सौ से अधिक लोगों की जान गई। जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडल लगातार गर्म हो रहा है और इसके चलते अंटार्कटिका के साथ ग्रीनलैंड में मौजूद बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है। अनुमान है कि 2050 तक अधिकांश ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। इनमें हिमालयी ग्लेशियर भी शामिल हैं। यह भारत के लिए एक बड़ी विपदा का संकेत है। हमें इसे लेकर चेतना ही होगा कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी असर ने भारत की दहलीज पर दस्तक दे दी है। दुखद यह है कि अब भी हमारे कार्य व्यवहार पर स्थितिवादी हवावी दिख रहा है। जलवायु परिवर्तन के मुख्य

कारक प्रदूषण के मुद्दे पर नीति निर्माताओं ने गंभीरता तो दिखाई, पर अभी उसके अपेक्षित नतीजे नहीं दिखे हैं। इसका कारण समाज में जागरूकता की कमी है। यदि प्राकृतिक संपदा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी उदासीनता दूर नहीं हुई तो भविष्य भयावह हो सकता है। चूंकि आजकल जेर लोकलुभावन नीतियों पर है इसलिए पर्यावरण की दशा सुधारने के लिए सख्त फैसले नहीं लिए जा रहे हैं।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसलीय अवशेष यानी पराली जलाए जाने से सर्दियों के मौसम में वायुमंडल घुुरी तरह प्रदूषित हो जाता है। सब इससे परिचित हैं कि पराली जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाईऑक्साइड के साथ अन्य विषैले गैसों का उत्सर्जन होता है, लेकिन उस पर रोक नहीं लग पा रही है। पराली जलाने की समस्या आज की नहीं, दशकों पुरानी है। राजनीतिक कारणों से न तो हरियाणा सरकार ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाना जरूरी समझा और न ही पंजाब सरकार ने। वे शत्रुमुर्गी रवैया अपनाए रखीं। जब इसके खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोग सक्रिय हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकारों की कुंभकर्णी नौद टूटी। यदि समय रहते किसानों को पराली जलने से होने वाले खतरों से अवगत कराया जाता और आम जनता को उन सभी कारणों से परिचित करवाया जाता जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो



अवधेश राजपूत

बेहतर होता।

हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि जलवायु परिवर्तन के कारण आदिकाल से जीवनदायिनी रहीं हमारी नदियां आज दम तोड़ने की कगार पर हैं। तमाम नदियां अब नष्टप्रायः हैं। हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की वजह से गंगा और यमुना की सहायक जलधाराएं तेजी से सूख रही हैं। इसके लिए आम लोग भी दोषी हैं। हम जहां नदियों की पूजा करते हैं वहीं उन्हें प्रदूषित करने से भी बाज नहीं आते। आखिर प्रतिमाओं के विसर्जन के समय यह ख्याल क्यों नहीं आता कि उनमें इस्तेमाल होने वाले रसायन और अन्य हानिकारक पदार्थ नदियों को जहरीला बनाते हैं? मुश्किल यह है कि शासन-प्रशासन धार्मिक आस्था के चलते प्रतिमाओं के विसर्जन के खिलाफ कोई कदम उठाने का साहस नहीं करता। यह अच्छा हुआ कि एनजीटी ने गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगा दी, लेकिन देखा है कि प्रशासन उस पर अमल कर पाता है या नहीं?

पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान

चलाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ही लाल किले की प्राचीर से इसके खिलाफ मुहिम चलाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी उन्होंने दुनिया को इस अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन रोकने के मामले में बातें करने का समय निकल चुका है, अब काम करके दिखाने का समय है। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को देखते हुए देर से सही, एक दुरुस्त फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने आम आदमी के रोजगार को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसा कदम नहीं उठाया है। चूंकि प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण छोटे-छोटे उद्योग करते हैं इसलिए उनके निर्माण पर यकायक पाबंदी लगती तो लाखों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता। राज्य सरकारों को यह समझना चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक के चलन को रोकने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। क्षरणशील न होने के कारण प्लास्टिक सैकड़ों साल ज्यों का त्यों बना रहता है। इससे पानी भी दूषित होता है और मिट्टी भी। प्लास्टिक अवशेष नदियों के जरिये समुद्र तक पहुंचते हैं और उनमें मौजूद जैव विविधता को बर्बाद करते हैं।

## काम न करने के कारगर नुस्खे

हार्य-व्यंग्य



यदि किसी कर्मचारी के सिर पर उसके बॉस ने वरदहस्त रखा हुआ हो तो उसे अपनी जाँब को लेकर फालतू की टेंशन नहीं पालनी पड़ती और कोई काम भी नहीं करना पड़ता। मुझे अपने

एक मित्र के श्रीमुख से जब यह अलौकिक ज्ञान सुनने को मिला तो मैंने पलटकर प्रश्न किया, 'यार, मुझको भी अपने बॉस को पटाने की तरकीब बताओ। मेरा बॉस तो हमेशा ही मुझसे चिढ़ा रहता है।' मित्र ने पूछा, तुम्हारा बॉस महिला है या पुरुष!'

मैंने प्रतिप्रश्न किया, 'क्या दोनों को प्रसन्न करने के अलग-अलग फार्मूले हैं?' वह बोला, 'भाई, मैंस मामले में जेंडर इन्क्वैलिटी नहीं चलती।' मैंने कहा, 'वैसे मेरा बॉस पुरुष है। वह अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता। समझ लो, टफ किस्म का केस है।' मित्र अपनी

जुबान से अतिशय आत्मविश्वास की चारुनी टपकता हुआ बोला, 'कितना भी टफ हो, आखिर है तो ईसान ही। मैं अपने बॉस साल के सेवकाल में एक से बढ़कर एक खूबत बॉसिज को पटाने का तजुर्बा रखता हूँ। तुम भी अगर मेरे कहे अनुसार चलोगे तो सदा सुखी रहोगे और कितना भी काम हो, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा।'

मैं भी अपने संकोच की पोटली का मुँह खोलते हुए उससे बोला, 'दोस्त, कहीं मेरा दांव उलटा पड़ गया तो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैदूंगा। तुम तो जानते ही हो, मुझे ये सारे दंद-फंद बिल्कुल नहीं आते।'

मेरा मित्र ठहके लगाता हुआ कहने लगा, 'हिम्मत क्यों रहते हो? मैं तुम्हें कुछ सूत्र बताऊँगा। मेरे पास सिद्ध फार्मूला है। तुम भी कल से ही उनके अनुसार



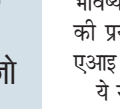
सूर्यकुमार पांडेय

अपने कार्यस्थल पर सदा ही टेंशनित रहने वालों के लाभार्थ एक गोपनीय विद्या का खुलासा

चलना शुरू कर दो। अगर मेरे सिखाए हुए सूत्र कारगर साबित नहीं हो पाए तो मैं अपनी मूँहें मुंडवा लूँगा।' मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। मूँह सूखा, मूँह का एक बाल तक नहीं था। फिर भी उस रोज मेरे उस मित्र ने जो तत्वज्ञान दिया था, उन पर अमल करने के बाद मैं आज परम सुखी प्राणी हूँ। जो नौकरी मुझे काटने दौड़ती थी, अब मुझे उसमें रस आने लगा है। अपने कार्यस्थल पर सदा टेंशनित रहने वालों के लाभार्थ मैं इस गोपनीय विद्या का खुलासा कर रहा हूँ। इसे स्वयं तो अपनाएं हीं, अरिों के बीच भी इसका प्रचार-प्रसार करते रहिए। लोगों के लाभार्थ मैं बॉस वशीकरण मंत्र के सूत्र पेश कर रहा हूँ।

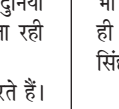
अपने बॉस से कलीग्स की चुगली करने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दें। अगर आपका निजी मकान हो तो उसको किराये पर उठाकर अपने बॉस के मोहल्ले में किराये का मकान ले लें। इस तरह सामीप्य का लाभ उठाइए। आप अपने बॉस के दरवाजे पर बिना नागा किए पहुंचिए। सुबह-शाम का एक चक्कर आपको ऑफिस की चकरावन्ती से मुक्ति दिलाने में सहयोगी बन जाएगा।

तथ्य-कथ्य



धूमपान करने वालों में ई-सिगरेट के उपभोक्ता आंकड़े फीसद में

स्रोत: स्टैटिस्टा ग्लोबल कंज्यूमर सर्वे



ब्राजील 4

भारत 5

स्पेन 8

जापान 10

जर्मनी 11

इटली 12

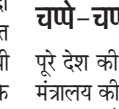
ब्रिटेन 13

अमेरिका 13

फ्रांस 14

चीन 20

राजंरग



नहीं लेना चाहते थे। जाहिर है कि पंजाब की सियासत में किनारे हुए सिद्ध की फिलहाल पड़ोसी हरियाणा के चुनाव में भी चुप ही रहना पड़ेगा।

चप्पे-चप्पे पर नजर

पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे गृह मंत्रालय की नजर अब नॉर्थ ब्लॉक के भीतर भी चप्पे-चप्पे पर होगी। वैसे तो नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में आने-जाने वालों की सुरक्षा जांच पहले भी काफी मुस्तीदी से की जाती थी, लेकिन एक बार बिल्डिंग में घुस जाने के बाद कौन कहा जा रहा है, यह जानना संभव नहीं था। जाहिर है कि कई आर्गनुक किसी एक अधिकारी के नाम पर पास बनवाकर कई अधिकारियों के कमरे में घूमते नजर आते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं हो सकेगा। गृह मंत्रालय के सभी गलियारों में अब कैमरे लगाए जा रहें हैं। इन कैमरों के माध्यम से गलियारों में घूमने वाले हर एक शख्स पर नजर रखी जा सकेगी। इससे गृह मंत्रालय के भीतर बिना वजह घूमने वाले अपने अधिकारियों पर नजर रखना भी आसान होगा। यानी अपने कामकाजी समय में बेवजह खाली घूमना गृह मंत्रालय के अधिकारियों पर भी गाज गिरा सकता है।

नार्वे का सवाल

वैसे तो विश्व मंत्री एस जयशंकर की छवि बेहद गंभीर कूटनीति की है, लेकिन उनके साथ काम करने वाले करीबी लोग उनके मजाकिया और हल्के-फुल्के चुटीले अंदाज को भी बखूबी जानते हैं। पिछले दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कार्यक्रमों में घूमने वाले हर एक अंदाज खुलकर सामने आया।

मौका था जब फोरम के प्रेसिडेंट बॉर्ग ब्रेंडे जयशंकर का लाइव साक्षात्कार कर रहे थे। ब्रेंडे नार्वे के पूर्व विदेश मंत्री हैं। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने जयशंकर से पूछा कि क्या भारत एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर अपने पड़ोसी देशों के बीच तension हो रही समस्याओं को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करेगा? जयशंकर का जवाब था, यह बहुत ही 'नार्वेई' सवाल है। उनके इस जवाब पर पूरा हल ठहकों से गूँज उठा और ब्रेंडे भी थोड़ी देर के लिए असहज हो गए। असल में जयशंकर ने बहुत ही सकारात्मक भाव से श्रीलंका में तमिल समस्या के दौरान उनकी भूमिका और उसकी तरफ से की जा रही मध्यस्थता की कोशिशों को याद दिला दी थी।

अनदेखी पर रोस

बिहार में नीतीश सरकार से भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय नेताओं की नाराजगी अब मुखर होने लगी है। खासतौर पर पटना के कुछ इलाकों में जलप्रलय के बाद यह शिकायत और ज्यादा गहरी हो गई है। अभी तक केवल कार्यकर्ता और स्थानीय स्तर के नेताओं की शिकायत ही सुनने में आती थी कि नीतीश प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, लेकिन अब विधायक और यहां तक कि सांसदों में भी इस तरह का भाव दिखने लगा है। हाल ही में पटना शहर में भरे पानी को निकालने में राज्य सरकार की धीमी रफ्तार और भाजपा विधायकों व सांसदों के सुझावों पर अमल में देरी को लेकर इन नेताओं में सार्वजनिक तौर पर तो अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन पार्टी के भीतर ऐसी सुमधुमाहट काफ़ी जोरों से रही कि प्रशासन भाजपा नेताओं द्वारा सुझाए जा रहे उपायों को नजरअंदाज कर रहा है। पीए इतना अधिक है कि उसकी आवाज दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। अब देखा यही होगा कि इसका असर क्या होगा है।